लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद शराब की दुकानें सजीं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, शराब यूं ही नहीं है सरकार से लेकर व्यापारियों तक की पसंद, यहां समझिए इसका गणित

लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कई दुकानों को खोलने का दिया नया आदेश

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के 53182 मामले, 35994 एक्टिव, 15394 लोग ठीक हुए वहीं 1790 लोगों की हुई मौत

एफडब्ल्यूआईसीई ने वर्चुअल मीटिंग में तय की शूटिंग शुरू करने की गाइड लाईन, हर सेट पर डॉक्टर, नर्स और सुपरवाइजर की नियुक्ति अनिवार्य

युवराज न्यूज़ टुडे

RNI:- BIHHIN05409

NEWS TODAY Update

www.newstodayupdate.in

आपकी आवाज़

राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

वर्ष : 06 अंक : 08+07 तिथि : 07 मई 2020 मूल्य : निःशुल्क प्रधान संपादक : डा. राजेश अस्थाना – 9471005272, 8210595830

email: newstodaymth@gmail.com website : newstodayupdate.in

न्यूज़ टुडे लॉक डाऊन स्पेशल रोजाना अंक

न्यूज टुडे एक्सक्लूसिव :

लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद शराब की दुकानें सजीं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, शराब यूं ही नहीं है सरकार से लेकर व्यापारियों तक की पसंद, यहां समझिए इसका गणित

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,

लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद से जिस तरह शराब की दुकानें सजीं और सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए जिस तरह लोगों का हुजूम वहां जुटा वह किसी से छिपा नहीं है। दुकानों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई लेकिन राज्य सरकारों ने इसे खजाना भरने का जरिया जरूर बना लिया। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार की ओर से भी आग्रह किया जा रहा है कि उन्हें भी अपने यहां रखी शराब की बिक्री की अनुमति दी जाए। दरअसल होटल ही सबसे लंबे काल तक के लिए प्रभावित होने वाले हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी उनकी स्थिति सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में शराब बिक्री के जरिए जहां वह स्टॉक खाली करना चाहते हैं, वहीं इससे आने वाली राशि वेतन भुगतान समेत दूसरे कामों में आ सकती है।

हर दिन 700 करोड़ रुपये अल्कोहल की बिक्री से मिलता है टैक्स

सामान्य दिनों में हर प्रकार के अल्कोहल की बिक्री से राज्य सरकारों को रोजाना लगभग 700 करोड़ रुपए बतौर टैक्स मिलते हैं। इस प्रकार पिछले 40 दिनों में राज्य सरकारों को 28, 000 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। शराब उत्पादक कंपनियों के मुताबिक अल्कोहल की कुल बिक्री में लगभग 30 फीसद हिस्सेदारी होटल, रेस्टोरेंट, पब व बार की होती है।

नुकसान कम करने के लिए बार और रेस्टोरेंट को मिल सकती है बिक्री की इजाजत

इस नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार रेस्टोरेंट और बार मालिकों को शराब की रिटेल बिक्री की इजाजत देने पर विचार कर सकती है। होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरकार से इस प्रकार की मांग कर रही हैं। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट व बार से अल्कोहल की बिक्री के लिए राज्यों को अपने आबकारी नियमों में बदलाव करना होगा। रेस्टोरेंट, पब और बार को बोतलबंद शराब बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्हें सिर्फ शराब पिलाने का लाइसेंस दिया जाता है।

शराब की बिक्री से मिलने वाला टैक्स देश की जीडीपी का एक फीसद

रेस्टोरेंट व बार की मांग के पक्ष में अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां भी आ रही हैं। दरअसल स्टॉक नहीं निकलने पर इन कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ेगा। कनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआइएबीसी) के महानिदेशक विनोद गिरी के मुताबिक देश भर में अल्कोहल का कारोबार 4 लाख करोड़ से अधिक का है। टैक्स के रूप में सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों की सरकारों को मिलते हैं। यह राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के एक फीसद से अधिक है।

फाइव स्टॉर होटलों में है अच्छी खासी बिक्री

दिल्ली स्थित फाइव स्टॉर होटल ली मरेडियन के सीओओ तरुण ठुकराल ने बताया कि उनके होटल में अल्कोहल का कारोबार सालाना 5–6 करोड़ का है। बियर की एक्सपायरी होती है, इसलिए उन्हें बियर तो फेंकनी पड़ेगी, लेकिन वाइन व व्हिस्की की बोतल रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वे इन बोतलों को बेच नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें शराब या बियर की बंद बोतल बेचने की इजाजत नहीं है।

रेस्टोरेंट से भी हो सकती है बोतलबंद शराब की बिक्री

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रकुल कुमार ने बताया कि रेस्टोरेंट में रखी हुई बोतलबंद शराब की होम डिलीवरी और रिटेल में बेचने की इजाजत को लेकर कई राज्यों की सरकार से उनकी बातचीत चल रही है। सरकार उन्हें रिटेल बिक्री की इजाजत दे देती है तो शराब के लिए दुकानों पर लगने वाली भीड़ के कम होने के साथ उनके स्टॉक भी निकल जाएंगे और सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा।

कोरोना स्पेशल

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के 53182 मामले, 35994 एक्टिव, 15394 लोग ठीक हुए वहीं 1790 लोगों की हुई मौत

सुनील चौधरी,
संवाददाता,

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) के 53182 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 35, 994 एक्टिव केस हैं। 15,394 लोग ठीक हो गए हैं। 1790 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 16,758 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 3094 लोग ठीक हो गए हैं और 651 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुजरात में 6625 मामले सामने आ गए हैं। इनमें 1500 लोग ठीक हो गए हैं और 396 लोगों की मौत हो गई है। दल्ली में 5532 मामले सामने आए हैं। 1542 लोग ठीक हो गए हैं और 65 लोगों की मौत हो गई है।

एफडब्ल्यूआईसीई ने वर्चुअल मीटिंग में तय की शूटिंग शुरू करने की गाइड लाईन, हर सेट पर डॉक्टर, नर्स और सुपरवाइजर की नियुक्ति अनिवार्य

ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने एक वर्चुअल मीटिंग में फिल्मों की शूटिंग को कुछ सुरक्षा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शुरू करने पर चर्चा किया। हालांकि फिल्मों या धारावाहिको की शूटिंग जुलाई से पहले शुरू नहीं हो पायेगी। यह बैठक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाइज (एफडब्ल्यूआईसीई) के पदाधिकारियों की सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन– सिनटा (सीआईएनटीएए) के पदाधिकारियों के साथ हुई।

शूटिंग शुरू करने को लेकर जिन गाइडलाइन पर चर्चा हुई वो निम्नलिखित है:

◆सभी कलाकार अपने घर से ही मेकअप और स्टाइलिंग का काम करेंगे और सेट पर सिर्फ एक स्टाफ सदस्य के साथ ही आएंगे।
◆सभी फिल्मों के निर्माता अपनी सेट पर काम करने वाले हर एक सदस्य को 12 घंटे के शूट के दौरान चार मास्क उपलब्ध कराएंगे। ◆शूटिंग शुरू होने के 3 महीने तक सेट पर उन लोगों को काम ना करने दिया जाए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है।
◆हर सेट पर डॉक्टर नर्स और सुपरवाइजर की नियुक्ति अनिवार्य

एफडब्ल्यूआईसीई के प्रेसिडेंट बी.एन. तिवारी और जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे तथा ट्रेजरार गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव ने कहा कि सिंटा के साथ हमारी बैठक के बाद हमने सभी एसोसिएशंस के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि हम फिल्मों की शूटिंग कुछ दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही शुरू करेंगे। हम इन नियम और कानूनों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तथा राज्य सरकार को भेजेंगे। वही इसपर अंतिम फैसला लेंगे। फिलहाल हमारे वर्कर बिना उचित सुरक्षा के शूटिंग नहीं करेंगे।इसके लिए दो दिन बाद फिर एक बैठक आयोजित की जारही है।

इस गाइडलाइन में सभी निर्माताओं और निर्देशकों को अपने सेट पर कुछ नियमों का पालन करने का आदेश देने पर चर्चा हुई। इन निद. शों के तहत सेट पर पहुंचने वाले हर कलाकार और क्रू के सदस्य को अपनी सेहत का एक परीक्षण करवाना होगा। इस दौरान उनके शरीर का तापमान भी जांचा जाएगा। यह प्रक्रिया हर रोज दोहराई जाएगी। अगर कोई बात बिगड़ती है तो हर रोज सेट पर डॉक्टर और नर्स को भी रखने के निर्देश हैं। यह नियम शूटिंग शुरू होने के शुरुआती तीन महीने तक लागू रहेंगे।

शूटिंग शुरू होने का मोटा मोटा अंदाजा लगाते हुए एफडब्ल्यूआईसीई के प्रमुख बीएन तिवारी ने बताया की शूटिंग लगभग जुलाई तक शुरू हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'हम शूटिंग के लिए अपने किसी भी कर्मचारी की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते।' एफडब्ल्यूआईसीई के सचिव अशोक दुबे ने बताया कि मीटिंग में सेट पर काम करने

हजारीमल हाई स्कूल में बनाए गए रैन बसेरा से करीब एक दर्जन लोग निकलकर सीमा शुल्क कार्यालय पहुंचे

अफजल आलम
न्यूज टुडे,

हजारीमल हाई स्कूल में बनाए गए रैन बसेरा से करीब एक दर्जन लोग निकलकर सीमा शुल्क कार्यालय पहुंच गए। जिन्हें एसएसबी ने पकड़करम् पुनः रैन बसेरा पहुंचाया। बताया जाता है कि नेपाल के विभिन्न जिलों के उक्त सभी लोग रैन बसेरा में रह रहे थे।
सभी लोग एक साथ सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए रैन बसेरा से निकलकर नेपाल की तरफ निकल पड़े। ये सभी लोग मुख्य पथ के रास्ते सीमा शुल्क कार्यालय पहुंच गए। लेकिन रास्ते में उन्हें कहीं भी नहीं रोका जा सका। आब्रजन कार्यालय के समीप बनाए गए जांच केंद्र पर जब चिकित्सकों ने स्क्रीनिग शुरू की तब जानकारी मिली कि ये लोग रैन बसेरा से भागकर नेपाल जा रहे हैं।
इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने उन्हें अभिरक्षा में लिया। फिर उन्हें रैन बसेरा पहुंचाया। इस संबंध में एसएसबी कमांडेंट प्रियब्रत शर्मा ने बताया कि करीब एक दर्जन लोग अचानक भारतीय कस्टम के समीप पहुंचे। दोनों देशों को जोड़ने वाली सरिसवा नदी पर बने मैत्री पुल के रास्ते नेपाल जाने का प्रयास कर रहे थे।
वहीं रक्सौल थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि इसकी जानकरीं नही है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवान पकड़े होंगे तो क्वारंटाइन सेंटर को सौंप दिया होगा। नगरपरिषद कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने बताया कि वहां नगरपरिषद के दो कर्मचारी भोजन पानी और अन्य सुविधा के लिए तैनात किए हैं। उक्त लोगों ने बताया कि कुछ लोग रात के अंधेरे में भाग गए थे। जिसे एसएसबी ने पकड़ कर सौंप दिया है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। इस संबंध में वहां तैनात लोगों से जवाब–तलब किया गया है।

बिहार सरकार से पांच सूत्री मांगों को लेकर रालोसपा ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका

आशीष राज,

कोरोना संक्रमण को ले लॉक डाउन एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे बिहार वासियों के हित में सरकार से पांच सूत्री मांगों को लेकर बिहार में रालोसपा ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा वैशाली में खुद मौजूद रहे, जबकि अन्य जिलों में पार्टी के पदाधिकारी थे। वैशाली में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए जंदाहा बाजार के गांधी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया।
कुशवाहा ने बताया कि सरकार से पांच सूत्री मांगों को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपने घर के आस–पास स्थित चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत जंदाहा में भी पुतला दहन किया गया। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों एवं अन्य लोगों को जल्द वापसी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, गुजरात सहित अन्य राज्यों में बिहारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को शीघ्र रोके जाने, बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्री सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने, जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं डाली गई है उनके खाता में दो हजार रुपये भेजने तथा जिनके खाता में पूर्व में एक हजार रुपये भेजे गए गए हैं, उनके खाते में फिर एक हजार भेजने एवं प्राकृतिक प्रकोप से किसानों के हुए नुकसान की शीघ्र भरपाई किए जाने की मांग शामिल हैं।

1247 छात्रों को लेकर कोटा से स्पेशल ट्रेन पहुंची बापूधाम मोतिहारी, रेलवे के द्वारा रास्ते मे दी गयी सुविधाओं के साथ साथ मोतिहारी में दी गयी सुविधाओं को भी जमकर सराहा छात्रों ने

रिंकू गिरी,
संवाददाता

कोटा से 1247 छात्रों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन के आज सुबह मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुची। स्टेशन पहुचने पर छात्रों ने जमकर ताली बजाई। छात्रों को लेकर चली ट्रेन में पूर्वी चंपारण के अलावा पश्चिमी चंपारण एवं गोपालगंज के भी छात्र शामिल थे। इन छात्रों को सकुशल घर पहुचाने के लिए पूरे जिला प्रशासन के साथ साथ मेडिकल टीम भी स्टेशन पर मौजूद थी।
ट्रेन में छात्रों के बीच डिस्टेंसिङ्ग के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर भी सोशल डिस्टेंसिङ्ग का ख्याल रखते हुए इन छात्रों से पहले ट्रेन के बोगी में अपनी अपनी सीटों पर मौजूद रहते हुए एक फॉर्म पर अपनी डिटेल्स भरने को दिया गया। बाद में एक एक कर छात्र ट्रेन से उतरे और अपनी अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई।
पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी कपिल अशोक शीर्षत ने बताया कि दूसरे जिलो के छात्रों को हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद नाश्ता का पैकेट दिया जाएगा और बसों से उनके घरों तक छोड़ा जाएगा। वहीं छात्रों ने भी रेलवे के द्वारा रास्ते मे दी गयी सुविधाओं के साथ साथ मोतिहारी में दी गयी सुविधाओं को भी जमकर सराहा।

लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कई दुकानों को खोलने का दिया नया आदेश

लॉक डाउन के बीच बिहार सरकार ने नया बड़ा आदेश जारी किया है. बिहार सरकार के नए आदेश के बाद जिलाधिकारी कपिल अशेक शीर्षत ने नया आदेश जारी किया, जिसमें लॉकडाउन में बरती जा रही सख्ती में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर ये निर्देश दिया है.
बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकान चालू करने के आदेश दिए हैं.इसके अलावा मोबाइल दुकान ,कंप्यूटर दुकान, लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत दुकान चालू होंगे. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट स्टील बालू स्टोन गिट्टी सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत दी है.
हालांकि कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगायी गयी है. ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं. वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज खोला जा सकेगा. HSNP यानि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान अन. मंडल स्तर पर एक और जिला स्तर पर दो खोली जायेंगी . वहीं प्रदूषण जाँच केंद्र भी खोले जायेंगे.

बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 151 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया

सम्राट, संवाददाता

बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन के दौरान बिहार कैबिनेट की यह तीसरी बैठक थी। इसमें कुल सात एजेंडा पर मुहर लगी है। इसमें सबसे बड़ा निर्णय के रूप में सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 151 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया है।

इसके अलावा स्कूलों के रख रखाव आदि के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। बताया जाता है कि कैबिनेट ने जिला स्तरीय स्कूलों के अध्यापक को सालाना 12 लाख रुपये खर्च की स्वीकृति पर अपनी मुहर लगा दी है। प्रखंड स्तर के स्कूल के प्रिसिंपल को 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

यह राशि स्कूलों के रंग रोगन, बागवानी, बिजली बिल आदि के लिए दी गई राशि दी गई है। इसी तरह, बिहार विधान मंडल के बजट सत्र 2020 के सत्रावसान की स्वीकृति भी दी गई।

NEWS TODAY Update | न्यूज टुडे | Yuvaraj An Ideal Film Production
बस एक क्लिक कीजिए
देश दुनिया की खबर के साथ अपनी खबर भी देखिए
www.newstodayupdate.in
A Fast Growing Web News Portal
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

रजि० कार्यालय : अष्ठाना निवास, मठिया जिरात, मोतिहारी-845401
समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें- 9471005272

Yuvaraj Media & Entertainment
बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830